

उत्तर-पूर्व के लिये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) लॉन्च किया गया

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने माल और सीमा शुल्क निकासी को अधिक कुशल बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (NER) के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) का शुभारंभ किया।

- इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) के कार्यान्वयन से सीमा पार व्यापार में रुकने के समय एवं लागत को कम करके सीमा शुल्क निकासी **व्यापार समुदाय के सदस्यों एवं हतिधारकों को सशक्त** बनाया जाएगा।
 - इन LCS पर नरियात टोकरी में मुख्य रूप से **खनजि** एवं कृषि उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात टोकरी में **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सीमेंट एवं प्लास्टिक उत्पाद** शामिल हैं।
- व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1948 से स्थापित **भारत-बांग्लादेश** एवं **भारत-म्यांमार** सीमाओं पर इन LCS का डिजिटलीकरण, **एकट ईसट पॉलिसी** का पूरक है, सुरक्षा, कागज़ रहित लेन-देन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से बाज़ार संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ाता है।
 - **केंद्रीय अपरत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** ने **ऑप्टिकल फाइबर** या मोबाइल नेटवर्क के बनिा दूरदराज़ के स्थानों से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिये भारत-बांग्लादेश तथा भारत-म्यांमार सीमाओं के साथ वभिन्न LCS पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया गया है।

और पढ़ें... [एकट ईसट पॉलिसी](#)